



हर रिश्ते का रखे ख्याल...



## ओसवाल का कमाल कपड़ों में डाले नई जान

ओसवाल वॉशिंग रेंज के साथ कीजिये कपड़ों की ऐसी दमदार धुलाई जिससे रेशा-रेशा खिले, पर रंग न छूटे। ओसवाल से धोइए और कपड़ों को रखिए एकदम चकाचक!



बेहतर सफ़ाई



कपड़ों की देखभाल



पैसे की बचत



कपड़ों की चमक  
व रंग बरकरार



बरसों का विश्वास



ओसवाल सोप ग्रुप



अधिक जानकारी के लिए  
+91 91161 71956, 96802 01956  
पर कॉल करें

विपणन :  
उत्तम चंद देसराज

अब घर बैठे मँगवाए ओसवाल उत्पाद



OswalSoap.com पर जाएं या  
स्कैन करें और ओसवाल एप डाउनलोड करें





### विचार बिन्दु

कार्य ही सफलता की बुनियाद है। –पाब्लो पिकासो

# इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ता रुझान

क्या भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का सही समय आ गया है? ये सवाल इन दिनों हर उस शख्स के मन में आता है जो नई गाड़ी खरीदने की सोच रहा होता है। कुछ लोग उन्हें यह सलाह देते हुए मिल जाते हैं कि हैं कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक गाडियों का ही है तो उसी पर खर्च करो। वहीं कुछ लोग ऐसी सलाह देते हुए भी मिल जाते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अभी देश तैयार नहीं है और इसे खरीदने पर कई मुश्किलों का सामना करना पड सकता है। मगर यह सच है कि अब सडकों पर ट्रैफिक में काफी संख्या में बिजली से चलने वाले वाहन नज़र आने लगे हैं। शहरों में इलेक्ट्रिक रिक्शाओं की संख्या भी तेजी से बढ रही है। महंगी कारें ही नहीं बैटरी से चलने वाले छोटे स्कूटर भी लगातार अपनी बढी हुई उपस्थिति दर्शा रहे हैं। अब यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में देश में पेट्रोल और डीज़ल के वाहनों का स्थान इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से लेंगे। इसके लिये वाहन उद्योग और उपभोक्ता दोनों तैयार लग रहे हैं। उद्योग जगत का अनुमान है कि वर्ष 2०30 तक देश में कुल वाहनों की बिक्री में बैटरी से चलने वाले वाहनों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत तक हो जाएगी। अधिकृत आंकड़ों के अनुसार अभी देश में बैटरी से चलने वाले करीब 14 लाख वाहन सडकों पर हैं। राज्यस्थान में भी 82 हजार से अधिक ऐसे वाहन चल रहे हैं। भारी उद्योग के राज्य मंत्री ने पिछली बार राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया था कि 3 अगस्त 2०22 तक भारत में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर श्री-व्हीलर यानी ई-रिक्शा मौजूद हैं, जिसकी संख्या तब करीब 8 लाख थी। उसके बाद टू-व्हीलर का नंबर आता है जो पांच लाख से ऊपर है, और फिर चार पहियों वाली गाडियां आती हैं, जो 50 हजार से थोड़ी ज़्यादा संख्या में इस्तेमाल हो रही हैं। उसाहवर्धक आंकड़े बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री उसके पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले तीन गुना बढ़ी। जलवायु और पर्यावरण संरक्षण तथा कार्बनिक ईंधन के कम होते ख़ोतों के चलते दुनिया भर में पेट्रोल और डीज़ल के वाहनों की जगह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने के प्रयास चल रहे हैं। इन प्रयासों में बिजली से चलने वाले वाहनों की क्षमता बढ़ाने और उन्हें उपभोक्ताओं को वाज़िब दाम पर मुहैया कराना शामिल है। बिजली से चार्ज होकर चलने वाले वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिये केंद्र सरकारने पिछले काफी समय से क्रमवाा अनेक कदम उठाये हैं। इनमें एक है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लगने वाले जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाना। इसके अलावा चार्जिंग स्टेशनों की जगहों का चयन और उनके लिये स्थानीय निकायों के नियमों की व्यवस्था करना और बैटरी स्वेपिंग के विकल्प की संस्थानिक व्यवस्थाएं करना भी शामिल है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े आंकड़ों के साथ ही उन परेशानियों और चुनौतियों की भी चर्चाएं हो रही हैं हमारे सामने पड़ती हैं। इलेक्ट्रिक गाडियों की क़्रीमत पेट्रोल या डीज़ल गाडियों की तुलना में ज़्यादा होती है। खले ही सरकार इन पर अलग-अलग तरह की रियायतें दे रही है, लेकिन फिर भी इन्हें खरीदने के लिये टाहक को पेट्रोल-डीज़ल की गाडियों के मुकाबले अधिक दाम देने पडते हैं। बाज़ार के विशेषज्ञों का कहना है कि जब बिजली से चलने वाले वाहनों की बिक्री बढ़ेगी

बिजली से चार्ज होकर चलने वाले वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिये केंद्र सरकार ने पिछले काफी

समय से क्रमवार अनेक कदम उठाये हैं। इनमें एक

है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लगने वाले जीएसटी को 12

प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाना।

इसके अलावा चार्जिंग स्टेशनों की जगहों का चयन

और उनके लिये स्थानीय निकायों के नियमों की

व्यवस्था करना और बैटरी स्वेपिंग के विकल्प की

संस्थानिक व्यवस्थाएं करना भी शामिल हैं।

हालांकि सरकार ने पिछले साल प्रोडक्शन लिंकड ईसेंटिव (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी थी। यह योजना देश में एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) के निर्माण के लिए लाई गई, जिससे बैट्री की कीमतों को कम किया जा सके। देश में इलेक्ट्रिक गाडियों के लिए चार्जिंग स्टेशन की भारी कमी अभी देखने को मिलती है। जिस तरह हमें हर हाइवे या सडक पर पेट्रोल पंप दिख जाते हैं, उसके मुकाबले चार्जिंग स्टेशन बहुत ही कम जगहों पर मिलते हैं। यह स्वाभाविक ही है क्योंकि अभी बिजली से चलने वाले वाहनों की संख्या कम है। भारत सरकार के मुताबिक देशभर में इस समय 1740 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन चल रहे हैं। कई बार यह सुझाव दिया जाता है कि पेट्रोल पंप पर ही इलेक्ट्रिक गाडियों को चार्ज करने की सुविधा भी दी जानी चाहिए। लेकिन इसमें एक बड़ी चुनौती यह है कि इलेक्ट्रिक गाडियों को चार्ज करने में एक से पांच घंटे का समय लगता है। ऐसे में बिजली के वाहनों को चार्ज करना किसी गाड़ी में पेट्रोल, डीज़ल या सीपनजी डलवाने जितना तेज़ी से नहीं हो सकता। इसके अलावा घर पर वाहन की बैट्री को चार्ज करने में भी अलग तरह की चुनौतियां हैं। आमतौर पर दोपहिया गाडियों या ई-रिक्शा की बैटरी को चार्ज घरों में ही चार्ज करते हैं। इसमें लंबा वक़्त लगता है इसलिए सुबह गाड़ी तैयार रखने के लिए उसे रात में चार्ज पर लगा दिया जाता है। चार्जिंग स्टेशन की कमी के साथ ही गाडियों की रेंज को लेकर भी ड्राइवरों के मन में डर पैदा होता है। अक्सर लंबी दूरी तक गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर इलेक्ट्रिक गाडियों की कम रेंज से परेशान होते दिखते हैं। लेकिन अब धीरे-धीरे तकनीकी कुशलता से यह रेंज बढ़ाई जा रही है। ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफ़िसिएंसि के मुताबिक दोपहिया इलेक्ट्रिक गाडियों की रेंज 84 किलोमीटर प्रति चार्ज बताई गई है। वहीं चोपहिया इलेक्ट्रिक गाडियों की औसत रेंज 150 से 3०0 किलोमीटर प्रति चार्ज बताई गई है। सरकार का कहना है कि बेहतर बैट्री और ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन लगावा कर इस समस्या को दूर किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाडियों में हर कंपनी अपने अलग-अलग चार्जिंग पोर्ट देती हैं। इससे इलेक्ट्रिक गाडियों के लिए यूनिवर्सल चार्जिंग सिस्टम बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। भारत के ईवी मार्केट में अभी भी चार्जिंग पोर्ट के लिए कोई एक मानक तय नहीं किया गया है। यह दिक्कत सबसे ज़्यादा दोपहिया इलेक्ट्रिक गाडियों दिखती है जहां अलग-अलग तरह की बैट्री और उनके अलग-अलग चार्जिंग पोर्ट बाज़ार में मिलते हैं। आने वाले समय में सरकार या बाज़ार स्वयं ऐसा मानक बना सकते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि गाडियों की परफॉमेंस में मौसम और तापमान का भी बड़ा योगदान होता है। बिजली के वाहनों के लिये तो मौसम तथा तापमान और ज़्यादा बड़े फैक्टर बन जाते हैं। सामान्यतौर पर किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए औसत तापमान की रेंज 15 से 40 डिग्री सेल्सियस मानी जाती है। लेकिन भारत में जहां पहाड़ी इलाकों में तापमान बेहद नीचे गिर जाता है तो वहीं पश्चिमी इलाकों में तापमान बहुत ऊपर रहता है। ऐसे में पूरे देश के लिए एक तरह की इलेैट्रिक गाडियों से काम नहीं चल सकता। मगर बढ़ते प्रदूषण और तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए यह तो तय है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक गाडियों का ही है।

बिजली से चलने वाहनों का समय आ गया है इसका प्रमाण है कि ऐसे वाहन दुनिया भर में अपना स्थान बनाने लगे हैं। उपलब्ध आंकड़ों और उनके आधार पर लगाए गये अनुमानों के अनुसार, इलेक्ट्रिक-वाहन की दुनिया भर में बिक्री ने पिछले साल एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है। उसने पहली बार लगभग 1० प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली। कुल बाजार में बिजली से चलने वाले वाहनों का हिस्सा मुख्यतः यूरोपीय संघ और चीन में बढ़ रहा है। पिछले साल इलेक्ट्रिक वाहनों की वैश्विक बिक्री लगभग 7.8 मिलियन यूनिट थी, जो उसके पिछले वर्ष से 6.8 प्रतिशत अधिक थी। इस परिवर्तन के दौर में भारत भी पीछे नहीं है जहां इन वाहनों के निर्माण और बिक्री में तेजी आ रही है। इसके लिये सरकारी स्तर पर जो प्रारम्भिक तैयारियां की गई हैं वह भी मददगार साबित हो रही है। नयी तकनीक वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और संचालन के लिये कानूनों में आवश्यक संशोधन किये गये हैं तथा उनकी बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं। आम तौर पर आधारभूत ढांचा तैयार करने में शासन तंत्र बहुत धीमे काम करता है किन्तु यह जानना सुखकर है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की व्यवस्थाएं करने में बेहद त्वरित गति से भविष्य को ध्यान में रख कर काम हुआ है। उबर निजी निर्माण क्षेत्र भी पीछे नहीं है और वह भारतीय ग्राहकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिये तत्पर है। बाजार की प्रतिस्पर्धा भी इन वाहनों की गुणवत्ता तो सुनिश्चित करेगी ही साथ ही उनके दामों पर भी नियंत्रण रखेगी। बाजार के समीक्षकों का कहना है कि आने वाले समय में जब वाहनों की बिक्री का बॉल्यूम बढ़ेगा उससे भी इनके दामों में कमी आएगी। यह सभी के लिये लाभ का सौदा होगा और पर्यावरण के संरक्षण में एक लंबी छलांग भी होगी और इसमें भारत अग्रिम पंक्ति में खड़ा मिल सकता है।

—अतिथि संपादक, राजेन्द्र बोड़ा (वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक )

# बाजरा सहित मोटे अनाज की विदेशों में करनी होगी एग्रेसिव मार्केटिंग



डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

जंक फूड के जद में आए दुनिया के देशों को मोटे अनाज का महत्व समझाने की पहल तो भारत ने 2०18 को कदन वर्ष मानकर ही कर दी थी और उसी का परिणाम रहा कि मार्च, 2021 में भारत द्वारा मोटे अनाज के महत्व को एक बार फिर समझाने के लिए 2०23 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव रखा तो दुनिया के 72 देशों ने भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया। अब योजनाबद्ध तरीके से विदेशों में भारत के मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। दिसंबर में रोम में अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष का आगाज हो चुका है। विदेशीय धरती पर बायर सेलर मीट जैसे आयोजन आरंभ

कर दिए गए हैं। उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संवाद कायम करने की कार्ययोजना पर अमल शुरू हो गया है। दरअसल अब लोगों को समझ आने लगा है कि कुपोषण के खिलाफ मोटा अनाज हथियार के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है तो दूसरी ओर हाइपरटेंशन और शुगर जैसी बीमारियों में भी मोटा अनाज कारगर सिद्ध हो सकता है।

वह दिन दूर नहीं जब दुनिया के देश हमारे बाज़े के स्वाद से रबर होने लगेंगे। आज मोटे अनाज को देश और विदेश दोनों ही जगह लोकप्रिय बनाना शुरू हो गया है। अब भारत के मोटे अनाज खासतौर से बाजरा को दुनिया के देशों में पहुंचाने की पहल आरंभ हुई है। सरकार ने विदेशों में मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने और बाजरा आदि के निर्यात को बढ़ाने का पूरा रोजमैप तैयार कर क्रियान्वयन आरंभ कर दिया है। एपिडा सहित अन्य निर्यातक संस्थाओं द्वारा इसके लिए संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं तो विदेशों में रोड शो, फूड फेस्टिवल, कॉन्फेलेव आदि के आयोजन से मोटे अनाज से बने उत्पादों से विदेशियों को आकर्षित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास शुरू हो

गए हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सांसदों को मोटे अनाज से तैयार व्यंजनों से लंच दिया जा चुका है। अन्य आयोजनों में भी मोटे अनाज से तैयार व्यंजनों को भी प्रमुखता से स्थान दिया जा रहा है। बाजरा व अन्य मोटे अनाज और उनसे तैयार उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार तैयार करने की सकारात्मक शुरुआत हुई है जिसके परिणाम प्राप्त भी होने लगे हैं।

यही कोई चार-पांच दशक पुरानी बात होगी। संदर्भ तो राजस्थान से ही ले रहा हूं पर कमोबस यही स्थिति देश के अन्य प्रदेशों में भी रही होगी। जब घर पर कोई मेहमान आता था या तीज त्यौहार होता था तभी घर में मीठे के रूप में चॉनल और गेहूं की चपाती बना करती थी। अन्यथा दिन-प्रतिदिन का खाना तो सर्दियों में बाजरा-मक्का की रोटी, बाजरा की रावड़ी या मक्का का दलिया या गर्मियों में जौ का दलिया और इसके साथ इसी तरह से मोटे अनाज की रोटी और हरी सब्जियां, कढ़ी जिसे गांव देहात की बोली में खाटा कहकर पुकारा जाता था बड़े चाव के साथ के खाते थे। फिर एक दौर चला जब मोटे अनाज की जगह गेहूं ने ले ली और फिर आज तो लोग गेहूं चांवल को भी छोड़कर जंक

फूड पर जोर देने लगे हैं जिसके परिणाम साफ-साफ दिखाई देने लगे हैं। दवाइयों के सहारे जीवन गुजरने लगा है तो इम्यूनिटी भी बुरी तरह से प्रभावित होने लगी है। खैर यह तो रही एक बात।

अब यदि हम खेती किसानों की भी चर्चा करें तो देखेंगे कि मोटे अनाज की खेती कम लागत और कम पानी की खेती होती है। अब वह चाहे बाजरा हो, मक्का हो, रागी हा, ज्वार हो या ओर इसी तरह का मोटा अनाज। दूसरी बात यह कि इनमें रोग भी कम लगते हैं तो जहरीले कीटाणु नाशकों का उपयोग भी ना के बराबर ही होता है। इस सबके बावजूद एक बात और मोटे अनाज का रक्बा धीरे-धीरे घटने के बावजूद यदि बाज़े की ही बात करें तो सारी दुनिया में उत्पादित कुल बाज़े का 41 फीसद बाजरा हमारे देश में उत्पादित होता है।

राजस्थान में तो बाजरा खरीफ की प्रमुख फसलों में से एक है। आज सभी राजनीतिक दल और किसान समर्थक संगठन किसानों की आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो यह भी साफ हो जाना चाहिए कि मोटे अनाज के निर्यात की मार्केटिंग सही तरीके से होती है और इसके उत्पादों को बाज़ार में आक्रामक रणनीति के साथ उतारा जाता है तो

## ग्राम पंचायत घटोर व भाखरिया में बिजली संकट

बाप, (निर्स)। जोधपुर जिले में बाप समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत घटोर व भाखरिया में बीते डेड माह से बिजली समस्या से ग्रामीण बेहद परेशान है। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की भी बिजली के अभाव में पढ़ाई बाधित हो रही है।

घटोर के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि घटोर में करीब डेड महीने से विद्युत सप्लाई अनियमित बनी हुई है। जिसके कारण विद्यार्थियों के साथ आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुबह पांच बजे ही बिजली चली जाती है। दिन में भी लंबे समय तक बिजली सप्लाई बाधित रहती है। शाम के समय भी सुचारू रूप से बिजली नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों ने रोप्रकट करते हुए बताया कि डिस्कॉम कार्यालय में संपर्क करने पर संतोषजनक जवाब तक नहीं दिया जा रहा है। अगले माह 1० वी व 12वी की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। जिसकी तैयारी को लेकर बच्चों ने पड़नी पड़ रही है। लेकिन बिजली के अभाव में उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है।

इस दौरान बालमनान, शिबू खां, शैतानराम, मजीद खां, सदीक, हुजुर, अयूब, मेहरदीन, आरूफ, अश्वर आदि मौजूद रहे। इसी तरह भाखरिया के ग्रामीणों ने गांव स्थित जीएसएस पर प्रदर्शन किया तथा डिस्कॉम के

- बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की भी पढ़ाई बाधित हो रही है**
- घटोर के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर समस्या बताई**

एक्सपैडन के नाम का ज्ञापन वहां कार्यरत लाइनमैन को सौंपा। सरपंच पेंपो सहित ग्रामीणों ने बताया कि भाखरिया पंचायत में डिस्कॉम ने कृषि कनेक्शन फीडर से ही घरेलू कनेक्शन दे रखे है। इस वजह से आम उपभोक्ताओं को 6 से 7 घंटा बिजली ही मिल पा रही है। यह भी निर्बाध रूप से नहीं मिल पा रही है। इसमें भी बिजली आती जाती रहती है। बिजली के अभाव में लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

ग्रामीणों ने कहा कि घरेलू विद्युत लाइन नलकूप लाइन से अलग करके स्थाई समाधान किया जाए, अन्यथा ग्रामीण आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इस मौके पर चतुराराम, यासीन, याकुब, बाबुराम, असलम, अकरम, गनीखां, मौलाना जोसफ सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।

# ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 811वें सालाना उर्स की रौनक परवान चढ़ने लगी



राज्यपाल कलराज मिश्र के प्रमुख विशेषाधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने मजार शरीफ पर पहुंच कर राज्यपाल की तरफ से चादर पेश की।

ऐतिहासिक महफिल खाने में दरगाह दीवान की सदातों में दूसरी महफिल में कव्वालों ने ख्वाजा साहब की शान में सुफियाना कलाम पेश किए। देर रात्रि दरगाह दीवान जेनुल आबेदीन अली खान ने ख्वाजा साहब की पवित्र मजार पर गुसल की रस्म अदा की। राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से ख्वाजा

मोईनुद्दीन हसन चिश्ती के 811 वें सालाना उर्स के मौके पर मंगलवार को दरगाह पर चादर पेश की गई।

अजमेर में राज्यपाल के प्रमुख विशेषाधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने मंगलवार को मजार शरीफ पर पहुंच कर राज्यपाल की तरफ से चादर पेश की। उनके साथ परिसहाय स्वकाइन

लीडर राहुल भार्गव भी थे। जियारत सैय्यद बारि चिश्ती एवं सैय्यद वसीम चिश्ती ने करवाई। इस दौरान राज्यपाल मिश्र का संदेश भी पढ़कर उन्होंने सुनाया। राज्यपाल मिश्र ने इस अवसर पर अपने संदेश में प्रदेशवासियों के सुखद स्वास्थ्य, खुशहाली और संपन्नता की दुआ करते हुए देश-दुनिया

- राज्यपाल कलराज मिश्र, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इंद्रेश कुमार व रालोद प्रमुख चिराग पासवान की ओर से चादर पेश**

- राज्यपाल ने संदेश में प्रदेशवासियों के सुखद स्वास्थ्य, खुशहाली और संपन्नता की दुआ की**

से अजमेर आ रहे जाइरीन को सुबारकबाद भी दी।

ख्वाजा साहब के 811वें सालाना उर्स में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों विहार, उत्तर प्रदेश, कोलकाता, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल आदि से बड़ी संख्या में जायरीन के आने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री अनेक गहलोट की ओर से 811वें उर्स पर चादर बुधवार को पेश की जाएगी।

कर्म अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। दीवनी कार्य को टालना ठीक रहेगा। बरते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्य में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

सिंह परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्य पर नियंत्रण बढ़ेगा।

कन्या स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।



पंडित अनिल शर्मा

कुम्भ, मंगल-वृष, बुध-धनु, गुरु-मीन, शुक्र-मकर, शनि-कुम्भ, राहु-मेघ, केतु-तुला राशि में।
कुमार योग दिन 12:35 से रात्रि 8:05 तक है। रवियोग रात्रि 8:05 तक रहेगी। आज भद्रा दिन 11:35 तक रहेगी। आज विनायक चतुर्थी, श्रीगणेश पूजा और बसंत पंचमी, पंचक है।

**सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया:** लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:59 तक, शुभ 11:19 से 12:34 तक, चर 3:19 से 4:38 तक, लाभ 4:38 से सूर्यास्त तक।
**राहूकाल:** 12:०0 से 1:3० तक। सूर्योदय 7:2०, सूर्यास्त 5:58।

मेघ आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटक हुआ लग प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।

तुला व्यावसायिक कार्यों से संबंधित मामलों में सौच-विचार हो सकता है। उचित परामर्श मिलेगा। नवीन कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

वृष व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। अटके हुए कार्य बनने लगेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

वृश्चिक घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मिथुन नवीन कार्य के संबंध में सकारात्मक अश्वत्थान प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेगी। व्यावसायिक सफलता से मनोबल ऊंचा रहेगा। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

धनु घर-परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिचितों के सहयोग से वर्तमान का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनने लगेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कुंभ मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगे। आवश्यक कार्य योजनासुचारु बने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। शुभ कार्य के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है।

मीन घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।















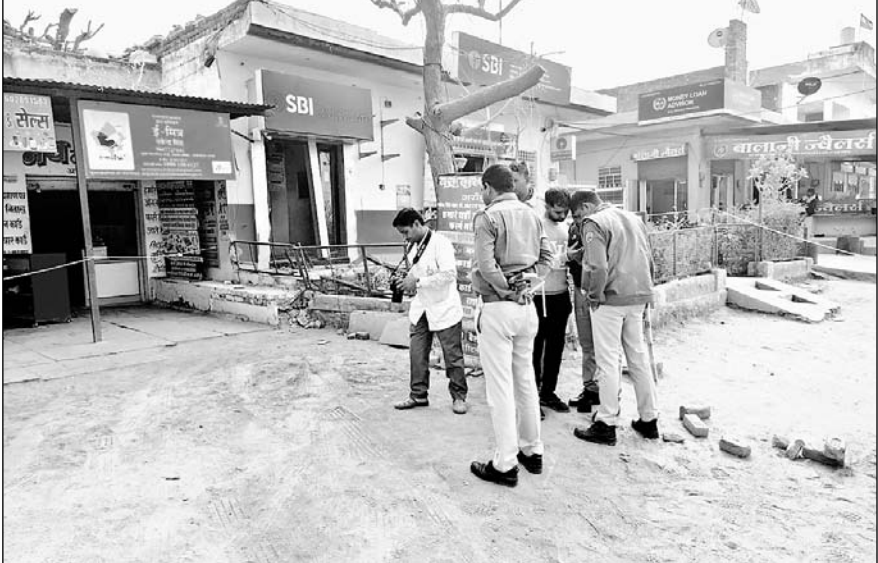
# एसबीआई का 3 1.6 5 लाख रुपये से भरा एटीएम उखाड़ ले गए नकाबपोश बदमाश

चोरों ने पहले एटीएम की बिजली काटी फिर सीसीटीवी पर काला रंग का स्प्रे कर चोरी को अंजाम दिया

अराई, (निसं)। पावर हाउस चौराहा स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर लगे एटीएम को अज्ञात चोर उखाड़कर ले गए। चोरों ने पहले एटीएम की बिजली काटी फिर सीसीटीवी कैमरों पर काला रंग का स्प्रे कर चोरी को अंजाम दिया।

सोमवार की देर रात्री को अज्ञात चोरों ने अराई एसबीआई की शाखा के बाहर लगे हुए एटीएम को उखाड़ कर केम्पर में डाल कर फरार हो गये। मामले को जानकारी मिलते ही अराई थाना प्रभारी गुमान सिंह मय जापने रात्रि को घटना स्थल पर पहुंचे एवं नाकाबन्दी करवाई, लेकिन चोरों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अराई पुलिस ने एफएसएल टीम को बुला कर तत्प्राकृतक रिपोर्ट मांगी है। पुलिस व एफएसएल टीम मिल कर संयुक्त जांच कर रही है। जानकारी अनुसार थाना प्रभारी गुमान सिंह ने बताया कि एटीएम में 31 लाख 65 हजार रुपये थे।

एसबीआई बैंक के समीप लगे



एटीएम लूट की वारदात के बाद पुलिस और एफएसएल टीम ने घटना स्थल पर साक्ष्य जुटाए।

एक सीसीटीवी केमरे में एटीएम लूट की घटना रात्रि 2:40 मिनट की है। घटनास्थल पर एक बोलेरो को पकड़ा है। यह लोग भीलवाड़ा

है। सबसे पहले दो नकाबपोश व्यक्ति बाहर आते हैं जो बैंक एवं एटीएम में लगे करीब चार से पांच सीसीटीवी केमरों पर ब्लेक स्प्रे करते हैं। चोरों ने

उसके बाद वहां का विद्युत कनेक्शन काट दिया। केम्पर गाड़ी को एटीएम के समीप लेकर आये और एटीएम को बांध कर बाहर घसीट लिया।



## पुलिस व एफएसएल टीम ने मिलकर संयुक्त जांच की

एटीएम को को सीधे केम्पर में पटका और फरार हो गये।

रात में गश्त के दौरान अराई पुलिस चौराहे पर एक अन्य गाड़ी का पीछा करती हुई पहुंची थी। अराई पुलिस को देखते ही गाड़ी चालक गाड़ी को लेकर किशनगढ़ की तरफ दौड़ा था। पुलिस ने गाड़ी का पीछा कर रुकवाया तो उसमें सुबर भरें थे। पुलिस ने इस गाड़ी को पकड़कर थाने ले आये। जहां पूछताछ की गई। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने एसबीआई बैंक के बाहर लगे एटीएम को उखाड़ लिया और त्वरित गति से फरार हो गये। एसबीआई बैंक के बाहर लगे एटीएम की सुरक्षा पर लगाया गया गाई मौके पर नहीं था। पुलिस उक्त गाई से पूछताछ कर रही है।

## हैड कांस्टेबल को टक्कर मारी

चूखू, (कासं)। यहां पुलिस लाइन में तैनात एक हैड कांस्टेबल को एक शराबी ने कार की टक्कर मारकर घायल कर दिया। कोतवाली थाना में दी रिपोर्ट में ओमप्रकाश पुत्र श्योकर्ण जाट निवासी सिरसला हाल हैड कांस्टेबल पुलिस लाइन चूखू ने लिखा है कि वह अपनी बाईक लेकर बाजार की ओर जा रहा था। उसी समय भूजल विभाग में नौकरी करने वाले लक्ष्मणसिंह ने उसकी बाईक को कार की टक्कर मार दी। कार चालक लक्ष्मणसिंह शराब के नशे में था। टक्कर मारने के बाद घायल हैड कांस्टेबल को आरोपी अस्पताल भी नहीं ले गया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

# आठ लाख की चोरी का खुलासा, ट्रक चालक और रिश्तेदार गिरफ्तार

## 16 तोला सोना, एक किलो चांदी और 85 हजार से ज्यादा की नगदी चुराई थी

किलो चांदी और 85 हजार से ज्यादा की नगदी चुराई थी, जिस बारे में केस दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि मामले में चोरों का पता लगाने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला। तब घड़ाव गांव के पास में एक सटिच्य ट्रक सूने स्थान पर खड़ा नजर आया। जिस पर उसकी लोकेशन और फुटेजों को देखा तो पता लगा कि यह ट्रक अजमेर ब्यावर होते हुए बैंग चितौड़गढ़ तक नजर आया है। आखिरकार पुलिस ने ट्रक का पता लगाते हुए उसे एक वर्कशॉप में पड़ा

पाया। बाद में पुलिस ने ट्रक लाने वाले उसके चालक मालिक भीलवाड़ा के मांडलगढ़ स्थित लाडपुरा निवासी कालू कंजर पुत्र सुरेश कंजर को पकड़ा। इस पर उससे चोरी का खुलासा हुआ। इस काम में उसने अपने एक अन्य रिश्तेदार चितौड़गढ़ के मंडावरा बैंगू निवासी जितेंद्र पुत्र आसाराम कंजर का साथ होना बताया। पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लाई है।

पुलिस पुछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी कालू कंजर खुद ट्रक चलाने के साथ मालिक भी है। वह ट्रक को चोरी के लिए ही प्रयुक्त करता था। अपने किसी परिचित को साथ लेता और सूने मकानों की रैकी कर बाद में चोरी कर लेता। इसके बाद ट्रक लेकर फिर अपने गांव लौट आता।

# 29 जनवरी तक उत्कर्ष ऑनलाइन कोर्सेस पर छूट

जोधपुर, (कासं)। उत्कर्ष क्लासेस द्वारा 74वें गणतंत्र दिवस के गौरवमयी अवसर पर देश भर के विद्यार्थियों के लिए उत्कर्ष एप के सभी ऑनलाइन कोर्सेस पर दोहरा लाभ प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इसके तहत 25 से 29 जनवरी तक उत्कर्ष एप के 650 से अधिक ऑनलाइन कोर्सेस पर 90 प्रतिशत तक की छूट तथा लाइव कोर्स के साथ उसी कोर्स का रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स नि:शुल्क दिया जा रहा है। उत्कर्ष एप को अब तक 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी डाउनलोड कर चुके हैं तथा यह एप अपने कई यूनिक फीचर्स के कारण विद्यार्थियों का पसंदीदा एप है। उत्कर्ष क्लासेस के संस्थापक एवं निदेशक डॉ. निर्मल गहलोत ने देश भर के सभी विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए बताया कि इस अवसर पर संस्थान द्वारा रखे गए दोहरे लाभ ऑफर के अंतर्गत उत्कर्ष एप में उपलब्ध सभी केन्द्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं सहित विभिन्न प्रवेश



डॉ. निर्मल गहलोत

परीक्षाओं एवं स्कूली टय्युशन के ऑनलाइन कोर्सेस पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ ही जिन विद्यार्थियों को लाइव कोर्सेस के साथ तैयारी करने में रुचि है उन्हें वे ऑनलाइन कोर्स नाममात्र के शुल्क में मिलने के साथ ही उसी कोर्स का सम्पूर्ण रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स भी नि:शुल्क प्राप्त होगा। विद्यार्थी उत्कर्ष एप के ऑनलाइन कोर्सेस सीएससी या ई-मित्र से खरीदने

## लाइव कोर्स के साथ सम्पूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स नि:शुल्क

## 74वें गणतंत्र दिवस पर उत्कर्ष की दोहरी सौगात

पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त डिस्काउंट पाकर भी लाभान्वित हो सकते हैं। डिस्काउंट ऑफर के अतिरिक्त उत्कर्ष एप में प्रत्येक परीक्षा की तैयारी के लिए पाँच ऑनलाइन मॉडल टेस्ट पेपर्स भी नि:शुल्क उपलब्ध हैं।

डॉ. गहलोत ने बताया कि उत्कर्ष एप में आईएएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) इत्यादि के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा एवं बिहार के विभिन्न राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं सहित नीट-जेईई, क्लेट, सीयूईटी, डिफेंस, नर्सिंग, कृषि, न्यायपालिका परीक्षा, इजीनियरिंग के

ऑनलाइन कोर्सेस तथा सीबीएसई एवं विभिन्न राज्य बोर्ड के तहत कक्षा 6 से 12 तक (हिंदी व अंग्रेजी माध्यम) के ऑनलाइन टय्युशन कोर्सेस उपलब्ध हैं। इन सभी श्रेणियों पर यह दोहरा लाभ ऑफर दिया जा रहा है। डॉ. गहलोत ने जानकारी प्रदान की कि इस महा डिस्काउंट ऑफर के अलावा 28 जनवरी को प्रतियोगी परीक्षाओं की विभिन्न श्रेणियों को लेकर ऑनलाइन मेगा इनामी टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा जिसमें देश भर के विद्यार्थी उत्कर्ष एप के माध्यम से बतौर प्रतिभागी भाग लेकर अपनी अपनी तैयारी की परख कर सकते हैं। प्रातः 8 बजे से रात्रि 12 बजे तक आयोजित इस टेस्ट की विभिन्न श्रेणियों में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से 1000 भाग्यशाली विजेताओं का चयन लक्की ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक विजेता को 500 रुपये का नकद प्रस्कार प्रदान किया जाएगा।

## दुष्कर्मियों को उम्रकैद

डूंगरपुर, (निसं)। छात्रा के दुष्कर्म करने के मामले पाँस्को कोर्ट ने 2 आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, कोर्ट ने दोषी चंदूलाल को 3 लाख 15 हजार 500 रुपये का जुर्माना और दोषी निलेश को 2 लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि पीड़ित ने थाने में 22 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट देकर बताया कि वो खेत में घास काटा रही है थी। तब आरोपी चंदूलाल और निलेश बाइक लेकर आये। इसके बाद उसे जब्तन बाइक पर बिठाकर विष्णु मंदिर के पास ले जाकर पीड़िता के साथ चंदू ने दुष्कर्म किया। वहीं, निलेश ने चंदू का साथ दिया। इसके बाद पीड़िता ने थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ़ रेप का मामला दर्ज करवाया था।

## शराब की 402 पेटियों से भरा ट्रक पकड़ा, दो गिरफ्तार

श्रीगंगानगर, (निसं)। आबकारी पुलिस ने पंजाब से गुजरात जा रही 402 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब जब्त की है। यह कार्रवाई नेशनल हाईवे 62 पर चक 22 एमएल से पास नाकाबंदी के दौरान की गई। पंजाब निवासी ट्रक चालक और परिचालक को मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी डॉ. नरेंद्रकुमार थोरी ने बताया कि आबकारी निरीक्षक मनीष पारीक, आबकारी ग्रामीण थानाधिकारी जयदयाल यादव, थानाधिकारी बनवारी लाल सैनी की ओर से मुखाबिरी की सूचना पर गश्त करते हुए नाकाबंदी की गई।

जानकारी के अनुसार सूरतगढ़ रोड नेशनल हाईवे 62 पर गांव 22 एमएल के पास नाकाबंदी की गई। इस दौरान पंजाब से गुजरात जा रहे ट्रक की तलाशी ली गई। ट्रक में अनार के सूखे छिलकों से भरे प्लास्टिक कट्टों के नीचे छिपाई 402 पेटियों में पंजाब निर्मित अवैध

## अनार के सूखे छिलकों से भरे प्लास्टिक कट्टों के नीचे छिपाई थी शराब

अंग्रेजी शराब की 4824 विभिन्न ब्रांड की बोतलें बरामद की गईं। ट्रक के ड्राइवर सुवासिंह सिंह व उसके साथी परमजीत सिंह को मौके पर दस्तयाब किया गया। वहीं ट्रक, इसमें भरे अनार के सूखे छिलकों तथा अंग्रेजी शराब को जब्त कर आबकारी एन्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को मंगलवार को अदालत में पेशकर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इस रैकेट की तह तक जाया जा सके। उल्लेखनीय है कि राजियासर पुलिस ने भी पिछले सप्ताह ऐसा ही ट्रक पकड़ा था, जिसमें 500 से ज्यादा पेटी थी और वह नमक की आड़ में ले जाई जा रही थी।

## नगदी छीनने वाले चार गिरफ्तार

धौलपुर, (निस)। धौलपुर शहर की सरत थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भरतपुर बाईपास रोड ओवरब्रिज के पास से ट्रक चालक को बंधक बनाकर रुपए छीनकर भागने वाले चार आरोपियों को घटना के महज 4 घण्टे में ही गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

सदर थाना प्रभारी हनुमान सहाय ने बताया कि 23 जनवरी को भरतपुर बाईपास रोड ओवर ब्रिज के पास से ट्रक चालक को बंधक बनाकर रुपए छीनकर भागने वाले 4 आरोपियों को घटना के महज 4 घण्टे के अन्तराल में ही आरोपी अरसेन पुत मान सिंह गुर्जर निवासी भीका का पुरा मौरोली, अतवीर सिंह पुत्र हरिसाद गुर्जर निवासी महात्मानन्द की बगौची पुराना शहर धौलपुर, नरवीर पुत्र हरिप्रसाद गुर्जर निवासी महात्मानन्द की बगौची पुराना शहर धौलपुर, सतीश पुत्र पूरन सिंह गुर्जर निवासी मसूदपुर थाना सहाय छोला जिला मुरैना को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई।

# बेटे के बाद अब महिला ने तोड़ा दम

हनुमानगढ़, (निसं)। अफ़ीम तस्करों के पीलीबंगा के बाई 9 में घर में पेट्रोल छिड़क कर दंपती और बेटे को ज़िंदा जलाने के मामले में बेटे के बाद अब झुलसी महिला की भी मौत गई। गंभीर रूप से झुलसी महिला का बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा था। सात वर्षीय बेटे की पहले ही मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि पीलीबंगा के बाई 9 निवासी जसवीर दास उर्फ मही, उसकी पत्नी मनप्रीत कौर और बेटा एकमजीत दास 19 जनवरी को अलमुबह करीब साढ़े पांच बजे घर के कमरे में सो रहे थे। उसी समय किसी ने घर में पेट्रोल छिड़क आग लगा दी। आग लगने से कमरे में बेड पर सो रहे पति-पत्नी और बेटा झुलस गए। तीनों को झुलसी अवस्था में पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया। यहां से हनुमानगढ़ के गवर्नमेंट जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यहां से मनप्रीत कौर और एकमजीत को हायर सेंटर बीकानेर रेफर कर दिया। वहीं, जसवीर दास को भर्ती कर इलाज शुरू किया। उसी दिन बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान एकमजीत दास ने दम तोड़ दिया। महिला ने भी रात को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

जसवीर दास ने पुलिस को बताया था कि वह पहले चिट्ठे का नशा करता था। तब वह जिनसे चिट्ठा खरीदता था, अब उन्हीं लोगों ने उसकी गली में चिट्ठा

## तस्करों ने पेट्रोल छिड़क कर लगाई थी आग

## बीकानेर में चल रहा था इलाज

बेचना शुरू कर दिया था। जब उसने उन लोगों को चिट्ठा बेचने से रोका तो उन लोगों ने हाथपाई की। तब इन लोगों ने धमकी दी कि वे उसे देख लेंगे। यही लोग बाल्टी में पेट्रोल भरकर उसके घर आए और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मात्र 6 घंटे में पड़ोसी राज्य पंजाब से शारज सिंह उर्फ गौरा (27) पुत्र बाजसिंह मजबूबी निवासी झोरखेड़ा पोसब बहाबवाला तहसील अंबोहर हाल किराएदार ढाणी चिराग पीएस अबोहर सिटी-1 जिला फाजिल्का (पंजाब) व उसके पिता बाजसिंह (53) पुत्र मुकंद सिंह को बापदी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि जसवीर दास उर्फ मही के साथ उनका चिट्ठा खरीद के रुपयों का विवाद था। जसवीर दास ने रुपए देने से मना कर दिया। इस पर रंजिशवश उन्होंने बाल्टी में भर पेट्रोल जसवीर दास उर्फ मही के शिराशरीर मकान में फेंककर लाइटर से आग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में अन्य लोगों के भी संलिप्त होने की जानकारी दी।

## अनिश्चितकालीन धरना जारी

सांचोर, (निसं)। सांचोर उपखंड कार्यालय भारतमाला परियोजना नेशनल हाईवे गुजरात सिक्स लाइन प्रोजेक्ट गुजरात बॉर्डर सेक्शन नंबर एनएच 754 अमृतसर से जामनगर इकोनामिक कॉरिडोर राजस्थान ईपीसी मॉड फेस फस्ट निर्माणधीन कंपनी के द्वारा डीपीआर के अनुसार कार्य नहीं करने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना

मंगलवार को दूसरे दिन जारी रहा। एसडीएम के मार्फत नितिन गडकरी मंत्री रोड एवं ट्रांसपोर्ट नेशनल हाईवे के नाम ज्ञापन दिया। भारतमाला नेशनल हाईवे घोडाला व डीपीआर एग्जेंटमेंट प्रोफाइल पर कार्य करवाने की मांग को लेकर गलत कार्य की जांच करने की मांग की है। वहीं डीपी आर एवं ड्राइंग की लागत ने वेरिएशन कंपनी अपने बिल में से भुगतान करना था परंतु इसी समय तक कंपनी एमएसपी आधारित ईजीनियर एनएचआई अधिकारियों द्वारा भारी रिश्तत लेकर इस प्रकार के अनियमितता को दबा दिया गया है। जिसकी जांच एनएचआई विलिंसेस से कराने की मांग की है। ग्राम लाछडी में कंपनी का बेस प्लॉट पिछले दो सालों से अवैध तरीके से नियम के विरुद्ध कृषि भूमि चल रहा है और कारोला में अवैध तरीका डामर प्लॉट पिछले 12 महीने से चल रहा है। जिसकी शिकायत उपखंड अधिकारी तहसीलदार को की। लेकिन एसडीएम सांचौर तहसीलदार द्वारा कंपनी को अनुचित फायदा लेकर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है।

# जेईई-मेन की परीक्षा शुरू, पहले दिन का पेपर सामान्य रहा

तीनों विषयों में से किसी भी विषय में विद्यार्थियों को किसी विशेष तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा

कोटा, (निसं)। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जा रही देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन का जनवरी सेशन की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई। कम्प्यूटर बेस्ड मोड पर कोटा में दो परीक्षा केन्द्रों पर यह परीक्षा हुई।

एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. बुजेश माहेश्वरी ने बताया कि स्टूडेंट्स के फीडबैक व सीसेट पर प्राप्त रिसर्प्सनेज के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पहले दिन का पेपर सामान्य रहा। तीनों विषयों में से किसी भी विषय में विद्यार्थियों को किसी विशेष तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। पेपर पैटर्न में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। 20 सवाल मल्टीपल च्वाइस के थे, जिसमें से 2-3 एसरशन-रिजनिंग (कथन और कारण) वाले थे। 10 न्यूमेरिकल वैल्यू के रहे। न्यूमेरिकल वैल्यू के 10 में से 5 सवाल ही हल करने थे।

कक्षा 11 से करीब 40 तथा कक्षा 12 से करीब 60 प्रतिशत सवाल पूछे गए। सुबह की पारी में फिजिक्स का पेपर सामान्य रहा। मैकेनिक्स से संबंधित काइनेमेटिक्स, एनएलएम रोटेशन से



जेईई मेंस के पेपर को लेकर छात्रों में उत्सुकता रही।

सवाल पूछे गए। इलास्टीसिटी थर्मोडायनेमिक्स के साथ-साथ इलास्टिसिटी और थर्मल एक्सपेंशन के प्रश्न पूछे गए। एरर, फ्लूड और साउंड

वेव से कोई सवाल नहीं था। जेईई-मेन एक्सक्यूलसिव टॉपिक्स में सेमी कंडक्टर और कम्प्यूटेशन सिस्टम के प्रश्न शामिल किए गए। एक सवाल फोटो

डायोड से भी रहा। केमेस्ट्री का पेपर सामान्य से कठिन रहा। पहले भाग में मैचिंग लिस्ट और एसरशन-रिजनिंग टाइप प्रश्न भी पूछे गए। फिजिकल

# जी-20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर संभागीय आयुक्त ने बैठक ली

## अधिकारियों ने सम्मेलन की तैयारियों को लेकर विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी

जोधपुर, (कासं)। आगामी 2 से 4 फरवरी तक जोधपुर में आयोजित जी-20 सम्मेलन को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा के लिए संभागीय आयुक्त कैलाशचन्द्र मीना की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई। इसमें सम्मेलन से जुड़े तमाम प्रबन्धों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़, उपायुक्त डॉ. अमृता दुहन, गौरव यादव, नगर निगम आयुक्त अरुण कुमार पुरोहित एवं अतुल प्रकाश, जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त नवनौत कुमार, एसीपी ट्राफिक चैनसिंह महेचा आदि अधिकारियों ने सम्मेलन की तैयारियों को लेकर विभागीय

गतिविधियों की जानकारी दी।

संभागीय आयुक्त ने सम्मेलन से संबंधित सभी स्थानों पर सौन्दर्यीकरण, मरम्मत आदि कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जन सहभागिता से दीवारों पर रंग-रोगन, स्वागत द्वार लगाने, चौराहों को सुसज्जित करने आदि के कार्य कराए जाएंगे। इस दौरान स्वागत में सहभागी बनने वाले शहरवासियों की जन सहभागिता के वीडियो भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

संभागीय आयुक्त ने जी 20 सम्मेलन के रूट तथा आयोजन स्थलों के आस-पास सीसीटीवी कैमरे लगवाने, सभी कार्यों की रफ्तार में तेजी लाने, कार्य को गति देने के लिए कार्मिकों की संख्या में

अभिवृद्धि करने के निर्देश देते हुए कहा कि 30 जनवरी से विशिष्टजनों का आगमन शुरू हो जाएगा। इसे देखते हुए कार्यों में गति लाए।

जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि सम्मेलन के दौरान जोधपुर के उद्योग और हस्तशिल्प की झलक दिखाने के लिए सालावास की दरियां, लाख की चुड़ियां, बाजरे का खेत आदि पर स्टॉल्स लगाए जाएंगे। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सम्मेलन को जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों पर विस्तार से जानकारी दी और बताया कि शहर को निखारने का कार्य अच्छी तरह चल रहा है और सम्मेलन से संबंधित कार्य तय समय पर पूर्ण कर लिए जाएंगे।

# विदाई समारोह से अभिभूत हुए सेशन न्यायाधीश

## जालोर के सेशन न्यायाधीश सिया रघुनाथदान को स्थानान्तरण पर अभिभाषक संघ ने दी विदाई

जालोर, (कासं)। जालोर अभिभाषक संघ की ओर से मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जालोर सिया रघुनाथदान के स्थानान्तरण समारोह पर उन्हें उत्साह पूर्वक विदाई दी। अभिभाषक संघ द्वारा रखे गये विदाई समारोह से सेशन न्यायाधीश अभिभूत नजर आये। जालोर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिया रघुनाथदान का स्थानान्तरण झालावाड़ होने पर अभिभाषक संघ जालोर की ओर से विदाई समारोह रखा गया।

जालोर शहर के एक होटल में आयोजित समारोह में जिला कलेक्टर निशत जैन, एसीपी हर्षवर्धन अग्रवाला, एडीजे तनसिंह चारण, पारिवारिक न्यायालय की न्यायाधीश रीत कुमारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश विरेन्द्र कुमार मीणा, सीजेएम महेश कुमार, एसीजेएम प्रथम चारण अशा व न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्षिता राठी मौजूद रही। समारोह में अभिभाषक संघ जालोर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार दवे ने अतिथियों का अभिनंदन किया। इसके बाद माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का

शुभारम्भ किया। समारोह में सेशन न्यायाधीश सिया रघुनाथदान का अतिवक्तओं ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। वरिष्ठ अधिवक्ता परमानंद शर्मा ने सेशन न्यायाधीश का तिलक व श्रीफल देकर स्वागत किया।

इस दौरान परमानंद शर्मा, बसंत कुमार गहलोत, अशोक जोशी, राजेन्द्र कुमार कच्छवाह, चैनराम पटेल, त्रिलोकचन्द मेहता, स्वामराम, नैनसिंह राजपुरोहित, मोहनसिंह राणावत, संतोष भारती, देवेन्द्रसिंह , मुमताज अली, तरुण सोलंकी, अभिभाषक संघ के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष इन्द्रजीत मेघवाल, सचिव रज्जब खान खोखर, कोषाध्यक्ष प्रवीण कुमार, पुस्तकालय अध्यक्ष गोपाल जोशी आदि मौजूद थे।







आरबीआई कहता है... जानकार बलिए, सतर्क रहिए!

अधिक जानकारी के लिए,  
<https://rbikehtahai.rbi.org.in/positivepay> पर जाएं  
फ्रीडबैक देने के लिए, [rbikehtahai@rbi.org.in](mailto:rbikehtahai@rbi.org.in) को लिखें

जनहित में जारी  
**भारतीय रिजर्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**  
[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

मात्र चार साल में पेपर लीक की 16-17 घटनाएं, आखिर दोषी कौन है?

‘पेपर लीक मामले में सी.एम. द्वारा अफसरों को क्लीन चिट देना गलत’

विधानसभा में विपक्षी दलों के और सदन के बाहर अपनों के निशाने पर गहलोत सरकार

जयपुर, 24 जनवरी (का.प्र.)। राजस्थान में पेपर लीक और नकल के प्रकरण को लेकर सरकार पूरी तरह से घिर गई है। विधानसभा में भाजपा और आरएलपी सदस्यों ने बजट सत्र शुरू होने के साथ ही सरकार की नाक में दम कर दिया है। वहीं सडक पर भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार के खिलाफ ताल ठोक दी है। ऐसे में चुनावी वर्ष में सरकार के लिए पेपर लीक कांड से बाहर निकलना सबसे मुश्किल काम हो गया है। पिछले दिनों सरकार के चिंतन शिविर में मंत्रियों तक ने खुलकर कहा था कि पेपर लीक का मुद्दा सरकार के सारे कामों पर पानी फेर देगा।

दरअसल राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 साल के दौरान ही पेपर लीक की 16 से 17 घटनाएं सामने आई हैं। ना केवल युवाओं में भारी रोष है, बल्कि विपक्षी दलों को भी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। एक के बाद एक पेपर लीक होने और इस वजह से परीक्षाएं रद्द करने के बावजूद भी सरकार इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, उल्टे अधिकारियों को क्लीनचिट देने और विपक्ष को गलत ठहराने में जुटी हुई है।

खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि 'पेपर लीक में कोई नेता

■ मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा पेपर लीक मामले में सरकारी अधिकारियों व मंत्रियों को क्लीन चिट देने का हर ओर से भारी विरोध हो रहा है।

■ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कह ही चुके हैं कि, जब कोई दोषी नहीं तो पेपर तिजोरी से बाहर कैसे आए। कांग्रेस के ही हरीश चौधरी ने भी कह दिया है कि, इन मामलों की सी.बी.आई. जांच कराई जाए।

■ भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार के सामने कई सबूत रख दिए और अब वे सड़कों पर भी उतर आए हैं।

■ पेपर लीक के कारण परीक्षाएं रद्द होने से युवा वर्ग में भारी नाराजगी है, जो चुनावी वर्ष में कांग्रेस को भारी पड़ सकती है।

और अधिकारी शामिल नहीं है। कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इस पर आक्रामक तेवर अख्तियार करते हुए कहा, जब कोई नेता या अधिकारी शामिल नहीं है, तो पेपर तिजोरी से बाहर कैसे आए। बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी, जो पहले से ही मुख्यमंत्री से कई मसलों पर नाराजगी जताते रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि राजस्थान में पेपर लीक और नकल के मामलों की जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी से

कराई जाए। यह कहकर एक तरह से उन्होंने राजस्थान की, जो एजेंसियां जांच कर रही है उन पर अविश्वास जता दिया है।

पेपर लीक और नकल के मामलों में अब तक भाजपा नेता और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आर.एल.पी.) नेता हनुमान बेनीवाल ही सरकार पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन पिछले दिनों जब सचिन पायलट ने पेपर लीक की घटनाओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, तो सरकार की मुश्किलें बढ़ गईं।

दरअसल सरकार की समस्या यह है कि इस चुनावी वर्ष में बजट सत्र के बाद सरकार को चुनावी तैयारियों में उतरना है और इधर एक के बाद एक हुई 16 से 17 पेपर लीक घटनाएं होने के बाद युवाओं की सरकार से भारी नाराजगी है। मुद्दा यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कोई भी अधिकारी और नेता पेपर लीक प्रकरण में शामिल नहीं है। ऐसे में यह सवाल पूछा जा रहा है कि जब कोई शामिल ही नहीं है तो रीट पेपर लीक मामले में डीपी जारेली को बर्खास्त क्यों किया गया और अगर दोषी होने के लिए बर्खास्त किया गया तो उन्हें कानूनी तौर पर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?

सदन में विपक्ष पेपर लीक कांड पर हंगामा कर रहा है और सी.बी.आई. जांच की मांग कर रहा है जिसे सरकार ने टुकरा दिया है कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। सरकार सदन में तो किसी भी तरह से विपक्ष को जवाब देकर चुप करा सकती है, लेकिन सदन के बाहर भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा एक के बाद एक सबूत सरकार के सामने रख रहे हैं और युवाओं को साथ लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने दीक्षा से लेकर जयपुर तक पेपर लीक प्रकरण मामले को लेकर प्रदर्शन किया। जिसमें

भारी भीड़ स्पष्ट है कि इस मसले को लेकर चुनावी वर्ष में ना तो भाजपा चुप्पी साधने वाली है और ना आरएलपी और अन्य दल। सरकार के बचाव में यह तर्क भी दिया जा रहा है कि केंद्र की परीक्षाओं और भाजपा सरकार के समय भी पेपर लीक हुए थे, लेकिन इससे यह सरकार पेपर लीक की 16-17 घटनाओं से पल्ला नहीं झाड़ सकती।

पिछले दिनों पेपर लीक प्रकरण के आरोपी के कोचिंग सेंटर और मकान पर सरकार ने भारी तोड़फोड़ की, लेकिन पेपर लीक के मुख्य आरोपियों को सरकार की नाक के नीचे से फरार हो जाना बड़े सवाल खड़े करता है। राज्य की जांच एजेंसियां अब तक इन आरोपियों तक पहुंचने में असफल रही हैं। इस सबके बाद भी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और कह रही है कि उन्होंने तीन लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं, इसलिए भाजपा को यह बात रास नहीं आ रही है।

दूसरी ओर एक के बाद एक युवा संगठनों की ओर से सड़कों पर किया जाने वाला प्रदर्शन बता रहा है कि सरकार को ओर से युवाओं से किए वादे आज भी अधूरे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि युवाओं के निशाने पर आ चुकी राज्य सरकार किस तरह से अपना दामन बचाती है।

पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री गहलोत की कार्यशैली पर सवाल उठाए

-विधानसभा संवाददाता- जयपुर, 24 जनवरी। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में अधिकारियों को क्लीन चिट देने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक हरीश चौधरी ने गलत ठहराया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए साफ कहा कि जांच पूरी हुए बिना ही अधिकारियों को क्लीन चिट देना गलत है। पेपर लीक होना बहुत बड़ा विषय है। किसी को भी क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल जांच जारी है।

■ हरीश चौधरी ने कहा कि ‘‘पेपर लीक होना बहुत बड़ा विषय है। बिना जांच पूरी हुए किसी को भी क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए।’’

हरीश चौधरी ने मंगलवार को सदन के भीतर भी विपक्ष द्वारा उठाई जा रही पेपरलीक की सीबीआई जांच की मांग का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि पेपरलीक गंभीर मसला है, युवाओं के

भविष्य का सवाल है। पेपरलीक काण्ड में कोई भी दोषी हो, चाहे सरकारी कर्माचरी, उद्योगपति, अधिकारी या सामान्य नागरिक। सरकार को उसकी पृष्ठभूमि को देखे बिना कार्रवाई करनी चाहिए। अभी पेपरलीक मुख्य मुद्दा है, लेकिन उस पर बहस ना होना ठीक नहीं है।

हमें विचार करना होगा कि परीक्षा पद्धति कैसे मजबूत बने, जिसमें पेपर लीक न हो। जिन लोगों ने पेपर आउट किया, उनमें भी सिर्फ चंद लोग हाथ लगे हैं, मुख्य आरोपी और उनके संरक्षकों को पकड़ने की जरूरत है।

छात्र संगठन बी.बी.सी. की डॉक्युमेंटरी की पूरे केरल...

( प्रथम पृष्ठ का शेष ) स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं देनी चाहिए यह एक राष्ट्र विरोधी कदम है तथा मुख्यमंत्री को इस मामले में दखल देकर स्क्रीनिंग रोकनी चाहिए। स्क्रीनिंग का मतलब होगा विदेशी ताकतों को भारत की एकता और अखंडता पर हमला करने का मौका देना।

मुरलीधरन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले उन आरोपों को खारिज कर चुका है जो डॉक्युमेंट्री में लगाए गए हैं। इन आरोपों का फिर से सार्वजनिक बहस में लाना सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने जैसे यह नफरत को बढ़ावा देना।’’ केन्द्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से आग्रह किया

कि तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं। केरल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के. सुरेन्द्रन ने मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन से हस्तक्षेप करने और स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं देने को कहा। उन्होंने कहा कि यह कदम ‘‘राजद्रोह’’ के समान है और डॉक्युमेंट्री का प्रदर्शन देश की एकता व अखंडता को खतरे में डाल रहे विदेशी प्रयासों का बढ़ावा देना होगा। केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने बी.बी.सी. ‘‘डॉक्युमेंट्री’’ ‘‘दुष्प्रचार’’ कह कर खारिज कर दिया और कहा कि बी.बी.सी. ने भारत में यह डॉक्युमेंट्री उपलब्ध नहीं करवाई थी, लेकिन यू-ट्यूब पर यह अवश्य कुछ समय के लिए उपलब्ध थी।

‘हम चलते...

( प्रथम पृष्ठ का शेष ) कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच की। कई बार उन्हें जांच के दौरान राजनीतिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा, लेकिन निष्पक्ष राजेन्द्र शेखर अपने कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नासंद करते थे।

बोफोर्स मामले का अपने परवान पर था, उस समय राजेन्द्र शेखर सी.बी.आई. के प्रमुख या डायरेक्टर थे। कांग्रेस सरकार के राज में राजीव गांधी पर बोफोर्स निर्माता से 64 करोड़ रू. की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। कैबिनेट सैक्रेटरी विनोद पाण्डे, जो राजस्थान कांडर के ही आई.ए.एस. थे ने एक उच्च पदस्थ बैठक बुलाई। रक्षा सचिव नरेश चन्द्र, जो राजस्थान कांडर के ही आई.ए.एस. थे, और एक और सचिव पी. दण्डपाणी तथा भुरेलाल और राजेन्द्र शेखर के साथ गहन मंथन कर रहे थे।

इस बैठक में पूरे मामले को संदेहपूर्ण माना गया और बोफोर्स पर भारत सरकार से गैर वाजिब ढंग से धोखाघड़ी करने का आरोप लगा।

तब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि सरकार इस रिश्वतखोरी में जो कोई भी लिप्त रहा हो, वह चाहे कितना बड़ा भी क्यों न हो, को नहीं छोड़ेगा। इन सब घोषणाओं से कांग्रेस, जो विपक्ष में थी, हिल चुकी थी।

जब बोफोर्स काण्ड की जांच सी.बी.आई. ने शुरू की तो थी तब मोहन कार्तेर सी.बी.आई. के निदेशक थे। कार्तेर पर जनता दल की सरकार का भरोसा नहीं था। कार्तेर को हटाकर राजेन्द्र शेखर को निदेशक लगाया गया था।

बोफोर्स का विवाद लम्बा चला और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आरोप-प्रत्यारोपण के बीच ही समय निकल गया। वी.पी. सिंह ने जिस मजबूती से मामला उठाया उसे कोई दिशा या मंजिल नहीं दिखा सका। इस बीच उनकी सरकार गिर गई और चन्द्रशेखर के नेतृत्व में दिल्ली में नई सरकार बन गई।

चन्द्रशेखर ने कुर्सी संभालते ही राजेन्द्र शेखर और एक वरिष्ठ आई.ए.एस. राजीव लोचन मिश्रा, जो राजस्थान से ही थे, को वापस राजस्थान भेजा। तब भैरोंसिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे और वह भी इन दोनों अधिकारियों को वापस राज्य में ही लाना चाहते थे।

राजेन्द्र शेखर खुशी-खुशी सी.बी.आई. का पद छोड़ आए। राजीव लोचन भी वापस आ गए। राजेन्द्र शेखर सी.बी.आई. जैसे महत्वपूर्ण पद के निदेशक रह चुकने के बाद राजस्थान पुलिस के महानिदेशक बन गए। लेकिन उन्होंने कभी इसे पदवीनति नहीं माना। पूर्व जन संपर्क अधिकारी लक्ष्मण

बोलिया, जो लम्बे समय पुलिस मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति में रहे स्वर्गीय शेखर को याद करते हुए कहते हैं: शेखर साहब नवाचार पसंद करते थे। सन् 1992 में उन्हीं की सोच के कारण राजस्थान पुलिस दिवस की शुरुआत हुई और तत्कालीन राज्यपाल डॉ. चैत्रा रेड्डी के हाथों पुलिस को सशस्त्र सेना की ही तरह ध्वज दिखाया गया। इससे पूर्व, 30 मार्च 1954 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने राजस्थान पुलिस को कलर (ध्वज) भेंट किया था।

शेखर साहब ने पुलिस का ध्येय वाक्य भी बदलकर ‘‘सेवार्थ कटिबद्धता’’ रखा और राजस्थान पुलिस पर एक फिल्म ‘‘सेवार्थ कटिबद्धता’’ बनाई।

लक्ष्मण बोलिया बताते हैं कि, स्वर्गीय शेखर ने अपने जीवन संघर्ष पर, ‘‘नॉट ए लाइसेंस टु किल’’ डिजाइनिंग मोमेन्ट्स, अनकेड्ड पेरट, मेमोरीज आर मेड ऑफ दिस तक हिन्दी में कल, आज और कल पुस्तकें लिखीं।

उन्होंने अपनी पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर ‘‘और जाते जाते’’ उप शीर्षक में प्रसिद्ध गायक और अभिनेता किशोर कुमार के गये गीत ‘‘चलते-चलते’’ का जिक्र करते हुए अमिलाथा व्यक्त की थी कि, उनकी मृत्यु पर्सदीक्षा कार्य रंथली पर ऐसे ही चलते-चलते हो जाए। उन्होंने महात्मा गांधी की बिड़ला हाउस में प्रार्थना करते हुए और पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. कलाम की इण्डियन इस्टीमेट्स ऑफ मैनेजमेंट में भाषण देते हुए मृत्यु का हवाला देते हुए लिखा, ‘‘वे दोनों महान आत्माएं थीं, लेकिन हमारे जैसे सामान्य प्राणियों के लिए अनुमानतः चुनिन्दा यही हो सकता है कि, हम चलते-चलते ही चल बसे।’’

राजेन्द्र शेखर के निधन पर भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर. मेहता ने शोक व्यक्त किया है।

मेहता ने कहा कि, स्वर्गीय राजेन्द्र शेखर भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर. मेहता ने शोक व्यक्त किया है।

मेहता ने कहा कि, पुलिस में पूरी निष्ठा और ईमानदारी दिखाते हुए उन्होंने अपने पद की गरिमा के अनुरूप कार्य किया और इस कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। मेहता ने कहा कि, पुलिस सेवा ने एक निष्ठावान व्यक्ति खो दिया है, वे आदर्श पुरुष था।

दिल्ली के ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

की नई तारीख तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया। नगर निगम द्वारा प्रथम मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव का यह दूसरा प्रयास था। आम आदमी पार्टी (आप), जिसे चुनाव में बहुमत मिला था, ने शैली ओबेरॉय तथा आले मोहम्मद इकबाल को क्रमशः मेयर तथा डिप्टी मेयर के पद के लिए अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा था। भाजपा की तरफ से रेखा गुप्ता मेयर तथा कमल बागरी डिप्टी मेयर के पद के लिए मैदान में हैं। छः जनवरी को इसी तरह के हंगामे के कारण चुनाव स्थगित करना पड़ा था। मार्शलस जब स्थिति को काबू करने में असफल रहे तो पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा ने चुनाव को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।

एक वीडियो शेयर करते हुए, आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा: ‘‘आज राजनाथ जी अपने निजी विचार व्यक्त कर रहे थे। ‘‘वे एक ऐसी पार्टी में हैं, जहाँ शीर्ष नेतृत्व उन्हें बताता है कि उन्हें क्या कहना है। मेरे ख्याल से, उनकी कोई पसंद-नापसंद नहीं है। उनका बयान उन आदेशों का परिणाम है, जो भाजपा का सर्वोच्च

( प्रथम पृष्ठ का शेष ) ‘‘इसलिये, मेरा मानना है कि बावचीत या संवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर बातचीत में ऐसे भी लोग होते ही हैं, जो हास्यास्पद बात कह देते हैं तथा इस मामले में मुझे बड़ा दुख है कि मुझे एक वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बारे में ऐसा कहना पड़ रहा है कि उन्होंने एक बेतुकी बात कही है।’’

उन्होंने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता (आजद) के साथ चले गये 90 प्रतिशत लोग कांग्रेस में वापस आ गये हैं तथा आजाद अकेले रह गये हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उन पर किये गये प्रहार को लेकर राहुल ने कहा कि वे ऐसा नहीं मानते कि राजनाथ जी अपने निजी विचार व्यक्त कर रहे थे। ‘‘वे एक ऐसी पार्टी में हैं, जहाँ शीर्ष नेतृत्व उन्हें बताता है कि उन्हें क्या कहना है। मेरे ख्याल से, उनकी कोई पसंद-नापसंद नहीं है। उनका बयान उन आदेशों का परिणाम है, जो भाजपा का सर्वोच्च

रिजिजू ने भारी आपत्ति जताई सुप्रीम....

( प्रथम पृष्ठ का शेष ) पारित कर दिया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में उक्त नैशनल जूडिशियल अपॉइन्टमेंट एक्ट रद्द कर दिया था।

इस पूरे मुद्दे ने उस समय एक नया आयाम ग्रहण कर लिया, जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुद्ध रूप से सरकार के वकील की भूमिका निभाते हुये, इस लड़ाई में कूद पड़े। और उन्होंने एक प्रकार से ‘‘भारतीय संविधान के मूलभूत ढाँचे’’ के उस सिद्धान्त पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, जो देश के न्यायशास्त्र की मार्गदर्शक भावभूमि के रूप में काम करता आ रहा है।

रिजिजू ने आज कहा कि वे ‘‘उचित समय पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे’’, लेकिन उन्होंने अपना दृष्टिकोण तो स्पष्ट कर ही दिया।

कानून मंत्री ने पत्रकारों को बताया, ‘‘‘रं तथा आई.बी. की गोपनीय तथा संवेदनशील रिपोर्टों को सार्वजनिक कर देना घोर चिन्ता का विषय है, जिस पर मैं उचित समय

पर अपनी प्रतिक्रिया दूँगा। आज का दिन (इसके लिये) उचित समय नहीं है।’’

रिजिजू ने कहा, अगर संबंधित अधिकारी जो किसी संवेदनशील स्थान पर वेश बदल कर देश के लिए काम कर रहा है तो अपनी रिपोर्टों के सार्वजनिक करने से पहले वह दो बार सोचेगा क्योंकि ऐसा करने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं।

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे चीफ जस्टिस से इस बारे में बात करेंगे तो उन्होंने कहा सी.जे.आई. से मेरी अक्सर मुलाकात होती रहती है। वे न्यायपालिका के प्रमुख हैं और ये सरकार व न्यायपालिका के बीच पुल का काम करते हैं। हमें साथ शामिल कर काम करना है। हम अलग-अलग काम नहीं कर सकते। यह एक विवादग्रस्त मसला जिस पर किसी और दिन बात करेंगे।

19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने उन पत्रों को सार्वजनिक कर दिया जिसमें तीन जजों की पदोन्नति पर सरकार का आपत्ति का विरोध

किया गया था। इन तीन प्रत्याशियों में से एक वकील है जिसने अपने समलैंगिक होने की घोषणा की थी।

इस रहस्योद्घाटन से सुरक्षा संस्थापन में बेचैनी देखी गई क्योंकि यह परम्परा रही है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिनकी नियुक्ति की जानी होती है और पूरी पूरी जांच पड़ताल की जाती है और गुप्तचर एजेंसियां इस रिपोर्ट को गुप्त रखती हैं।

सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यह अप्रत्याशित कदम उठाने से पहले चार दिन तक चर्चा की गई और इसके फायदे नुकसान को परखा था। जजों की नियुक्ति पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कटु तकरार का यह नवीनतम चरण है।

सरकार जजों की नियुक्ति में महती भूमिका चाहती है जो कि वर्ष 1993 से ही सुप्रीम कोर्ट के कोलौजियम का विशेषाधिकार बन गया है। कोलौजियम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जजों का एक पैनल है। सरकार का तर्क है कि

व्यवस्थापिका सर्वोच्च है क्योंकि यह जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है।

सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच संविधान को लेकर भी विवाद चलता रहता है कि इसके किस भाग को संसद बदल सकती है या फिर जजों की नियुक्ति के सिस्टम के लिए क्या बदलाव कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोलौजियम सिस्टम देश का कानून है जिसका पूर्णतया पालन किया जाना चाहिए।

रिजिजू अक्सर जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं होने की बात करती है। कल ही उन्होंने कहा था कि जजों को चुनाव लड़ने या जनता का सामना करने की जरूरत नहीं है। कानून मंत्री ने कल एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि, लोग आपको देख रहे हैं और जज कर रहे हैं। आपके फैसले, काम करने का तरीका, आप कैसे न्याय करते हैं लोग देख सकते हैं और राय बना सकते हैं।’’

रिजिजू अक्सर जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं होने की बात करती है। कल ही उन्होंने कहा था कि जजों को चुनाव लड़ने या जनता का सामना करने की जरूरत नहीं है। आपके फैसले, काम करने का तरीका, आप कैसे न्याय करते हैं लोग देख सकते हैं और राय बना सकते हैं।’’